



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

10-1-85

सं० 576]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 23, 1984/अग्रहायण 2, 1906

No. 576]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 23, 1984/AGRAHAYANA 2, 1906

इस भाग में निम्न सूची संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1984

अधिसूचना

का० आ० 878.—केन्द्रीय सरकार, अमृतसर आयाल
वक्स (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1982
(1982 का 50) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का
संक्षिप्त नाम अमृतसर आयाल वक्स (उपक्रमों का अर्जन
और अन्तरण) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त
होंगे।

2. परिभाषाएं इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से
अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम से अमृतसर आयाल वक्स (उपक्रमों
का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1982
(1982 का 50) अभिप्रेत है,

(ख) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और
परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. सूचना के लिए समय सीमा,—किसी निहित संपत्ति
का प्रत्येक बन्धकदार और विहित संपत्ति में या उसके संबंध
में कोई प्रभार या धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने
वाला प्रत्येक व्यक्ति, इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की
तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर आयुक्त के समक्ष ऐसे
बन्धक, प्रभार धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना
देगा:

परन्तु यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि
ऐसा बन्धकदार या कोई प्रभार धारणाधिकार या अन्य हित
धारण करने वाला व्यक्ति, उक्त पन्द्रह दिन की अवधि के
भीतर उक्त सूचना देने में पर्याप्त कारणों से निर्धारित रहता
है तो वह उस सूचना को पन्द्रह दिन को और अवधि के
भीतर प्राप्त कर सकेगा, उसके बाद नहीं।

4. सूचना की रीति (1) नियम 3 के अधीन आयुक्त
को दी जाने वाली प्रत्येक सूचना आयुक्त को संबंधित करके

लिखित रूप में और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात्:—

- (क) बन्धकदार/प्रभार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले व्यक्ति का नाम, वर्णन और पुरा पता;
- (ख) उस उपक्रम का नाम जिसकी बाबत दावा किया गया है;
- (ग) दावा की राशि (भारतीय मुद्रा में);
- (घ) हित यदि कोई हो, की विशिष्टियां जिसके द्वारा बन्धक, प्रभार, धारणाधिकार या अन्य हित प्रतिभूत है, विनिधान की अनुप्रमाणित प्रति द्वारा समर्थित होंगी;
- (ङ) पहले से ही प्राप्त राशि, यदि कोई हो जिसके साथ विशिष्टियां होंगी;
- (च) दावा से सुसंगत अन्य विशिष्टियां; और
- (छ) दावाकृत अनुतोष।

(2) सूचना दो प्रतियों में होंगी और वह वयस्थिति, बन्धकदार या किसी निहित संपत्ति में या उसके संबंध में प्रभार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले व्यक्ति या उसके सम्बंधित अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित होंगी।

(3) यदि निहित संपत्ति में या उसके संबंध में कोई प्रभार, धारणाधिकार या अन्य हित सृजित करने वाला कोई बिलेख या दस्तावेज अंग्रेजी या हिन्दी में सिवा किसी भाषा में है तो अंग्रेजी या हिन्दी में उसकी अनुलिपि भी जो उसके सही अनुवाद के रूप में अनुप्रमाणित होगी, प्रस्तुत की जाएगी।

(4) नियम 3 में निर्दिष्ट सूचना और उसके समर्थक दस्तावेज ब्लाक 12-ए जामनगर हाउस हटमेंट, अन्वर रोड, नई दिल्ली 110011 स्थित आयुक्त के कार्यालय में किसी कार्य दिवस का फाइल किए जा सकते हैं या आयुक्त का रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं।

(5) डाक द्वारा भेजी गई सूचना की वशा में पन्द्रह दिन की संरक्षण करने के प्रयोजनार्थ, वह तारीख जिसकी वह आयुक्त के कार्यालय में परिदत्त की जाती है, आयुक्त द्वारा प्राप्ति की तारीख समझी जाएगी, वह तारीख नहीं जिसकी वह उत्तमधर में रजिस्ट्रीकृत की जाती है।

5. निधियों आदि का प्रशासन—अमृतसर आरक्षक वर्क के संबंध में अमृतसर शहर मिल्स कम्पनी द्वारा स्थापित अविषय निधि, अधिवापिकी निधि, उपदान निधि, कचरापन या अन्य निधि के जमा खाने निधिवा जो अमृतसर आरक्षक वर्क के संबंध में अमृतसर शहर मिल्स कम्पनी द्वारा नियोजित

या प्रारूपिक रूप से नियोजित व्यक्ति या व्यक्तियों के फायदे के लिए हैं और जो धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी कम्पनी को अन्तर्गत हो गई हैं, सरकारी कम्पनी द्वारा संबंधित निधियों के खाते में जमा की जाएगी। इस प्रकार जमा की गई धनराशि का सरकारी कम्पनी द्वारा उपयोजन सर्वथा लागू नियमों और विनियमों के उपबन्धों तथा संबंधित निधियों को शासित करने वाली किसी विधि के अनुसार किया जाएगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोजन नहीं किया जाएगा।

[मिसिल संख्या 18/5/84 ई०श्री०पी०]

गिरीश प्रधान, अवर सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 22nd November, 1984

NOTIFICATION

G.S.R. 878(E).—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Amritsar Oil Works (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1982 (50 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules namely:—

1. Short title and commencements.—(1) These rules may be called the Amritsar Oil Works (Acquisition and Transfer of Undertakings) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Amritsar Oil Works (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1982 (50 of 1982);

(b) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Time limit for intimation.—Every mortgagee of any vested property and every person holding any charge or lien or other interest in or in relation to vested property shall give an intimation of such mortgage, charge, lien or other interest, to the Commissioner with fifteen days from the date of publication of these rules in the Official Gazette.

Provided that if the Commissioner is satisfied that such mortgagee or the person holding any charge, lien or other interest was prevented by sufficient cause from giving the above intimation within the said period of fifteen days he may receive the intimation within a further period of fifteen days and not thereafter.

4. Manner of intimation.—(1) Every intimation to be given to the Commissioner under rule 3 shall be in writing addressed to the Commissioner and shall contain the following particulars, namely:—

- (a) name, description and full address of the mortgagee/charge, lien or other interest holder ;
- (b) name of undertaking in respect of which the claim is made ;
- (c) amount of claim (in Indian currency) ;
- (d) particulars of the interest, if any, by which mortgage, charge, lien or other interest is secured, supported by an attested copy of the investment ;
- (e) amount, if any, already received, with particulars ;
- (f) any other particulars relevant to the claim ; and
- (g) relief claimed.

(2) The intimation shall be in duplicate and shall be duly signed and verified by the mortgagee or the person holding a charge, lien or other interest, in or in relation to any vested property, as the case may be, or by his duly authorised agent.

(3) If any deed or document creating a charge, lien or other interest, in or in relation to vested property, is in a language other than English or Hindi a transcript thereof in English or Hindi duly certified to be true translation shall also be furnished.

(4) The intimation referred to in rule 3 together with supporting documents may be filed in the office of the Commissioner at Block 12-A, Jamnagar House Hutments, Akbar Road, New Delhi-110011 on any working day or may be sent to the Commissioner by registered post with acknowledgement due.

(5) For the purpose of counting fifteen days in case of an intimation sent by post the date on which the same is delivered in the office of the Commissioner shall be treated as its date of receipt by the Commissioner and not the date on which it is registered in the post office.

5. Administration of funds etc.—The funds standing to the credit of provident fund, super-annuation fund, gratuity fund, welfare or other funds, established by the Amritsar Sugar Mills Company in relation to the Amritsar Oil Works for the benefit of such person or persons employed or formally employed by the Amritsar Sugar Mills Company in connection with the Amritsar Oil Works transferred to the Government company under subsection (1) of section 13 shall be credited by the Government company in the accounts of the respective funds. The money thus credited shall be utilised by the Government company strictly in accordance with the provisions of the rules and regulations applicable and any law governing the respective fund and shall not be utilised for any other purposes.

[F. No. 18/5/84-EOP]

GIREESH PRADHAN, Under Secy.

